पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की नीति 'बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने' की है और इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया जाएगा

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 115 दिनांक:29-08-2024 गुरूवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रण रेखा के पास खुशाल पोस्ट पर गोलीबारी शुरू हुई। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

बारिश से गुजरात में त्राहिमाम!

-कई जिलों में बाढ़ के हालात, 07 की मौत, सेना बचाव और राहत कार्य में जुटी

-गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश के साथ देश के 17 राज्यों में बारिश का अनुमान

नई दिल्ली/अहमदाबाद, (ईएमएस)। गुजरात में हुई भारी बारिश के चलते अनेक जिलों में बाढ़ के हालात हैं। सेना को बुलाया गया है और अनेक जगहों पर राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। बारिश के कारण गुजरात में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने गुजरात और कर्नाटक में भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही देश के 17 राज्यों के लिए बारिश होने का अनुमान जताया है।

गुजरात में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अनेक शहरों में जलभराव से बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इन दिनों मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, आणंद, मोरबी, खेड़ा समेत तमाम शहरों में जीवन अफरा-तफरी वाला हो गया है। आमजन भारी बारिश की मार झेल रहा है। बारिष से परेशान लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा मानो जल प्रलय के दौर में आ गए हों। बारिश की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत होने की खबर है।

गुजरात में बाढ़ के चलते अब तक करीब 15 हजार से भी अधिक लोगों को निचली बस्तियों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं करीब 300 लोगों को पानी में डूबने से बचाया गया है। आपात स्थिति को देखते हुए सेना बुलाई गई है, जो कि लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है। आगामी मौसम के हाल को देखते हुए 6 जिलों में सेना तैनात कर दी गई है। बहरहाल बारिश का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 22 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश के चलते वडोदरा के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

यातायात के साथ जनजीवन प्रभावित

भीषण बारिश के चलते यातायात तो ठप हो ही गया है, लेकिन इसके साथ ही जन-जीवन भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में अब तक औसत वार्षिक वर्षा का करीब 100 फीसदी पानी बरस चुका है। कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात जिले में औसत वार्षिक वर्षा से 100 फीसदी से अधिक बारिश हो चुकी है।

अनेक राज्यों में बारिश से जूझ रहे लोग

देश के अनेक हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मॉनसून की तेज रफ्तार उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक मूसलाधार बारिश करवा रही है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मॉनसून आने के साथ ही इन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर रेड अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट। अब लोग बारिश थमने की प्रार्थना और दुआएं करते देखे जा रहे हैं। बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ रही हैं और लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान और गुजरात में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश से हर तरफ त्रहिमाम मचा हुआ है। देश के 17 राज्यों जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, ओडिशा, मेघालय, तेलंगाना, नगालैंड, हिमाचल प्रदेश केरल और पंजाब शामिल हैं में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश का अनुमान है।

कोलकाता रेप-मर्डर पर राष्ट्रपति, निराश और डरी हुई हूं... बस बहुत हो गया

ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत को सुधारना होगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस के 20 दिन बाद बुधवार को पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत को बदलना होगा है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। पीड़ित में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछना होगा। अक्सर घृणित मानसिकता वाले लोग महिलाओं को अपने से कम समझते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया है। समाज की भूलने की यह सामूहिक आदत घृणित है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है।

'बंगाल जला तो यूपी, बिहार, दिल्ली और असम भी जलेंगे', ममता की चेतावनी - पीएम की कुर्सी हिला दूंगी

कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या की घटना को लेकर लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों और भाजपा द्वारा बुधवार को बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद से भड़कीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी है।

तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर यहां एक रैली में ममता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम लेकर आरोप लगाया कि आरजी कर मामले में कुछ लोग अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल को अशांत करने के लिए आग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा, उपद्रव को संदर्भ बनाकर राज्य में जारी विरोध प्रदर्शन के लिए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए ममता ने स्पष्ट कहा, 'याद रखिए, अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ-ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी (पीएम) कुर्सी हिला देंगे।'

ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की नीति 'बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने' की है और इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा, ताकि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित किया जा सके। बनर्जी ने कहा कि यदि राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं या इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में शनिवार से जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी, ताकि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके।

ममता ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि यह (बंगाल) बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश से प्यार है। वे हमारी तरह बात करते हैं और हमारी संस्कृति भी एक जैसी है। लेकिन, याद रखिए कि बांग्लादेश अलग देश है और भारत अलग देश है।

बंगाल में हिंसा का तांडवः बंद के विरोधी और समर्थक भिड़े, फायरिंग में दो घायल, कई गिरफ्तार

कोलकाता(ईएमएस)। भाजपा के आव्हान पर आज पश्चिम बंगाल बंद किया गया है। सड़कों पर बंद के समर्थक और विरोधी सड़कों पर उतरे हैं। भाजपा कार्यकर्ता बाजार और दुकाने बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं जबकि टीएमसी कार्यकर्ता बाजार खोलने का दवाब बना रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों में भिड़ंत भी हो गई। जिसमें ताबड़तोड़ की गई फायरिंग में दो भाजपा समर्थक बुरी तरह घायल हुए हैं। जिसे लहुलुहान की स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर पुलिस उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए लगातार लोगों को हिरासत में ले रही है। जबकि बस चालक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनकर बस चलाने को मजबूर हुए हैं। बंगाल बंद के दौरान सबसे गंभीर घटना उत्तर 24 परगना जिले के भाटापारा से सामने आई है, जहां दो समूहों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद एक स्थानीय भाजपा समर्थक रबी सिंह को गोली लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बैरकपुर से पूर्व लोकसभा सदस्य और भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया कि घायल समर्थक और उसके कुछ साथियों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रोक लिया और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। सिंह ने कहा, बंद को विफल करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही इलाके में आतंक मचा रहे हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है।

अगर बंगाल में बंद के असर की बात करें, तो इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं दुकानों के शटर गिरे नजर आ रहे हैं, तो कहीं खुले। इसके अलावा, लोग व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस बंद के विरोध में दुकानें खोली। उनका कहना है कि हम इस बंद का पालन नहीं करेंगे। इसके अलावा, ड्राइवर भी गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट पहना हुआ है। उनका कहना है कि अगर कहीं अप्रिय स्थिति पैदा होती है, तो हेलमेट उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर बंगाल में तनाव जारी है। पहले छात्र समुदाय ने इस घटना के विरोध में 'नबन्ना मार्च' निकाला। इसमें हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर गुस्सा जाहिर कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और अब इसके बाद बीजेपी ने आज (बुधवार) पूरे बंगाल में बंद का आह्वान किया है, जिसका तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया हैटीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर इस बंद का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमें देश को बचाना है, तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा।

दिनाजपुर में आगजनी तो मुर्शिदाबाद में बीजेपी समर्थकों की पिटाई

बता दें कि नबन्ना मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है। यह बंद 12 घंटे का है। टीएमसी इस बंद का विरोध कर रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। पुलिस हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा, उत्तर दिनाजपुर में बंगाल बंद के दौरान आगजनी की खबर सामने आई है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि आखिर इसे किसने अंजाम दिया। मुर्शिदाबाद में बीजेपी समर्थकों की पिटाई कर दी गई, वो लोगों से बंद करने की अपील कर रहे थे। बंगाल बंद पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल ने पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस सरकार का रवैया घिनौना है। सरकार कानून को नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। यह सरकार महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने अक्षम है। लिहाजा हमारा विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ जारी रहेगा।

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नबन्ना मार्च के दौरान गिरफ्तार हुए छात्रों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। उन्होंने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का विरोध जरूरी है।

आदमखोर भेड़ियों के खौफ में जी रहे 70 हजार ग्रामीण

6 बच्चों को मार चुका भेड़ियां

बहराइच (ईएमएस)। मैं अपने 7 साल के बेटे अयांश के साथ रात में आंगन में सो रही थी। तभी भेड़िया कब बच्चे को उठा ले गया, मुझे पता भी नहीं चला। जब नींद खुली तब देखा कि बेटा गायब था। घरवालों के साथ रातभर बेटे को खोजती रही, लेकिन नहीं मिला। सुबह गांव वालों ने बताया कि बेटे का शव खेत में पड़ा है। बेटे का पूरा सिर भेड़िया खा गया।

यह बातें रोती-बिलखती अयांश की मां रोली ने कही। वह बहराइच के खैरीघाट में रहती हैं। 48 घंटे में भेड़िए के हमले से यहां 2 लोगों की मौत हुई है। 47 दिन में भेड़ियों का झुंड 6 बच्चों सहित 7 लोगों का शिकार कर चुका है।

बहराइच की महसी तहसील में भेड़ियों का खौफ है। भेड़ियों का आतंक पहले 25 गांव से में ही था, लेकिन दो दिन में यह बढ़कर 35 गांव तक पहुंच गया। भेड़ियों का खौफ इतना है कि गांव वाले लाठी-डंडे लेकर रातभर पहरेदारी कर रहे हैं। वन और पुलिस विभाग के करीब 200 कर्मचारी खेतों और जंगलों में भेड़ियों की तलाश में जुड़े हैं। महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह ने खुद बंदूक लेकर भेड़िए की तलाश की, लेकिन हमले के बाद भेड़िए जंगल में भाग जाते हैं।

आदमखोर भेड़ियों का शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। इसके पहले 21 अगस्त की रात इसतरह की घटना गडरिया गांव में हुई थी। दादी और उसके दो जवान बेटों के बीच 8 साल की पोती खुशबू सो रही थी। रात करीब 11 बजे आदमखोर भेड़िए ने चुपके से हमला कर खुशबू को दबोच कर भाग गया। परिवार के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले वह आंखों से ओझल हो गया। रात भर पूरा गांव बच्ची की तलाश करता रहा। सुबह 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। उसके शरीर का करीब 60 फीसदी हिस्सा खा गए थे। बहराइच की महसी तहसील के हरदी और खैरीघाट इलाके में 35 से ज्यादा गांव हैं, जहां करीब 70 हजार की आबादी है। ये लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ में जी रहे हैं। ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी के किनारे जंगल-झाड़ियां हैं। इसमें भेड़िए छिपे रहते हैं।

सीबीआई ने आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आयकर विभाग (पटना और धनबाद) के प्रधान आयुक्त और चार अन्य को विभिन्न करदाताओं से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त संतोष कुमार को 10 लाख रुपये की कथित अवैध रिश्वत के लेन-देन के दौरान गिरफ्तार किया। उनके साथ चार अन्य गुरपाल सिंह, राजीव कुमार, अशोक चौरसिया और प्रणय को भी गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने कुमार के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है वह विभिन्न आयकरदाताओं से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांग रहे थे और ले भी रहे थे। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि यह भी आरोप है कि प्रधान आयकर आयुक्त (पटना और धनबाद) की तरफ से कई लोग काम कर रहे थे। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद पटना, धनबाद और नोएडा में करीब 21 स्थानों पर छापेमारी की जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री बरामद हुई।

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को एसजीपीसी ने कानूनी नोटिस भेजा

नई दिल्ली (ईएमएस)। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने पर कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि कट्टरपंथी सिखा उपदेशक जरनैल सिंह भिंडरावाला और सिख समुदाय के किसी अन्य व्यक्ति ने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की है। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिनके शासन काल में 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था।

इस फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। वह इस फिल्म की निर्माताओं में भी शामिल हैं। फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज हुआ था और फिल्म के 6 सितंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमनबीर सिंह सियाली द्वारा भेजे गए नोटिस में फिल्म निर्माताओं से फिल्म से सिख विरोधी भावनाओं को दर्शाने वाले दृश्यों को हटाने के लिए कहा गया है। ट्रेलर को सार्वजनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के साथ-साथ सिख समुदाय से लिखित माफी मांगने की भी मांग की गई है।

एसजीपीसी ने कहा, ''ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिनमें सिख पोशाक में कुछ किरदारों को असॉल्ट राइफलों से लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है।'' नोटिस में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं है जो साबित करता हो कि भिंडरावाले ने कभी किसी से ऐसे शब्द कहे हों। एसजीपीसी ने नोटिस में कहा है कि फिल्म सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सिख धर्म के बारे में गलत शिक्षा देने का एक साधन साबित होगी। नोटिस में कहा गया है कि फिल्म में सिख धर्म के इतिहास के काले दिनों को दिखाया गया है।

हिमाचल में पंजाबी को दूसरी भाषा बनाने की मांग

पूर्व सीएम चन्नी बोले- मैं मुख्यमंत्री सुक्खू से मिला, विचार करने का दिया आश्वासन

जालंधर(ईएमएस)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने दो दिन पहले मुलाकात की थी। ये मुलाकात हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई थी। इस मुलाकात का मकसद पंजाबी भाषा को बढ़ावा देना था।

कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच पंजाबी भाषा को हिमाचल प्रदेश की दूसरी भाषा के तौर पर पहचान देने को लेकर चन्नी ने मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा की है। इसे लेकर आज पूर्व सीएम और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने जानकारी सांझा की है। चन्नी ने कहा- हिमाचल प्रदेश में बड़ा तबका ऐसा जो पंजाबी भाषी है, जिसके चलते राज्य में पंजाब भाषा को दूसरी भाषा के तौर पर दर्जा दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी

28,602 करोड़ में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर

- 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना

नई दिल्ली(ईएमएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। इसमें 1।52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार इन परियोजनाओं पर 28,602 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मंजूरी दी है। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी के साथ ही राजस्थान के जोधपुर-पाली में डवलप किए जाएंगे। इन औद्योगिक केंद्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

अब मोहन भागवत को भी मिलेगी मोदी-शाह जैसी सुरक्षा

केंद्र ने आरएसएस प्रमुख की सिक्योरिटी बढ़ाई

नई दिल्ली(ईएमएस)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसी सुरक्षा मिलेगी। दरअसल, गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत की सुरक्षा को जेड प्लस से बढ़ाकर एएसएल (एडवांस्ड सिक्योरिटी लिएजॉन) में बदल दिया है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख को अभी तक जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी।

गृह मंत्रालय ने कई जगहों पर मोहन भागवत की सुरक्षा में ढिलाई देखी, जिसके बाद ही उन्होंने नए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर काम करना शुरू किया और आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि कई भारत विरोध संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं। उनकी सुरक्षा बढ़ाने जाने को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसकी जानकारी दी गई है। अब नई सुरक्षा श्रेणी के अनुसार, सीआईएसएफ की टीम उस स्थान पर पहले से ही मौजूद रहेंगी, जहां मोहन भागवत दौरा करेंगे।

2015 में दी गई थी जेड-प्लस सुरक्षा

मोहन भागवत को जून 2015 में जेड-प्लस की सुरक्षा दी गई थी। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा कवर देने का आदेश दिया था। हालांकि, उस समय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कर्मियों और वाहनों की कमी के कारण उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जेड-प्लस सुरक्षा में 36 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं जिसमें एनएसजी के भी 10 कमांडो होते हैं। बता दें कि एएसएल श्रेणी की सुरक्षा में संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभाग जैसी स्थानीय एजेंसियां शामिल होती हैं। जिस स्थान पर मोहन भागवत कार्यक्रम के लिए जाएगें, वहां पहले से ही एक टीम मौके का निरीक्षण करने जाएगी। उनके ग्रीन सिग्नल देने के बाद ही मोहन भागवत उस कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे।

आईटी इंजीनियर ने 15वीं मंजिल पर बने फ्लैट की बालकनी से कूदकर आत्महत्या की

नई दिल्ली (ईएमएस)। डिप्रेशन का सामना कर रहे एक आईटी इंजीनियर ने नोएडा सेक्टर-75 स्थित पंचशील प्रतिष्ठा सोसाइटी के 15वीं मंजिल पर बने फ्लैट की बालकनी से कूदकर जान दे दी। यह घटना मंगलवार की है। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या का कारण जानने के लिए सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पंचशील प्रतिष्ठा सोसाइटी के टावर संख्या आठ के फ्लैट नंबर 1508 में 36 वर्षीय पंकज पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। मंगलवार शाम 3 बजे के करीब 15वीं मंजिल से कूदकर पंकज ने आत्महत्या कर ली। किसी के गिरने की आवाज सुनकर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड भागकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक पंकज की मौत हो चुकी थी।

पंकज सेक्टर-126 स्थित एक कंपनी में आईटी इंजीनियर थे। पुलिस सोसाइटी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है। जिस समय हादसा हुआ पंकज की पत्नी जालंधर गई हुई थीं। पत्नी को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। वह नोएडा के लिए निकल चुकी हैं।

बताया जा रहा है कि मैसेज और मेल के माध्यम से पंकज ने घटना के पहले पत्नी से संवाद भी किया था। मेल में पंकज ने अपने लैपटॉप समेत पासवर्ड और बैंक संबंधी जानकारी पत्नी को दी है। आत्महत्या के लिए इंजीनियर ने पत्नी से माफी भी मांगी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पंकज बीते कुछ दिनों से डिप्रेशन की दवा भी ले रहे थे। वह मूलरूप से पंजाब जालंधर के रहने वाले थे।

राजविंदर सिंह भट्टी बने सीआईएसएफ के नए डीजी

नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार के पुलिस महानिदेशक रहे राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का नया डीजी बनाया गया है। वहीं दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ की कमान संभालते रहेंगे। आरएस भट्टी दिसंबर 2022 से बिहार के पुलिस महानिदेशक थे। भट्टी 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक सीआईएसएफ में होगा। आरएस भट्टी की छवि एक कड़क अधिकारी की रही है। बिहार के डीजीपी बनने से पहले वो पटना के सिटी एसपी और सीवान, पूर्णिया जिलों के एसपी रह चुके थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट से पत्रकार को मिला न्याय.....महाराष्ट्र सरकार दे मुआवजा

मुंबई (ईएमएस)। जबरन वसूली के मामले में ठाणे के एक पत्रकार की गिरफ्तारी को अवैध बताकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध के आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और पुलिस के लिए यह समझदारी होगी कि वह पहले इसकी सत्यता की जांच कर ले। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार को पत्रकार अभिजीत पडले को 25,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि उन्हें तीन साल तक जेल में रखने के बाद उनकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था।

अदालत ने पत्रकार को गिरफ्तार करने वाले शहर के वकोला पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच शुरू करने आदेश दिया है। पडाले ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की थी क्योंकि पुलिस ने पहले उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी नहीं किया था। धारा 41ए के तहत, पुलिस किसी मामले में आरोपी व्यक्ति को अपना बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है और उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं होगी, जब तक कि पुलिस यह न मान ले कि गिरफ्तारी जरूरी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि पडले के खिलाफ अपराध सात साल से कम कारावास से दंडनीय था और इसके बाद धारा 41ए के तहत पडले को नोटिस दिया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा कि पुलिस ने नोटिस तैयार किया था लेकिन नोटिस तामील नहीं किया गया।

चार दिन में छोड़ दें असम, बाहरी मुसलमानों को मिल रही धमकी

-हिंदी भाषियों के खिलाफ 30 संगठन सड़क पर उतरे

गुवाहाटी,(ईएमएस)। नागांव दुष्कर्म मामले के बाद असम में अलग-अलग जगह बच्चियों और महिलाओं से यौन शोषण और छेड़छाड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें हिंदी भाषी बाहरी आरोपी है। स्थानीय लोगों ने इसे अस्मिता का मुद्दा बना लिया है। ऊपरी असम के दस जिलों में मियां और मारवाड़ी समेत हिंदी भाषी बाहरियों के खिलाफ 30 संगठन सड़क पर उतर आए हैं। वह घर-घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और मियांओं को असम छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इस मुहिम को 29 संगठनों का समर्थन मिला हुआ है, इनमें मुस्लिम संगठन, ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद, असम सम्मिलित मुस्लिम परिषद भी शामिल हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है, राज्य को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा।

शिवसागर समेत सभी दस जिलों में पुलिस ने सामुदायिक तनाव फैलाने वालों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। इनके खिलाफ ऑपरेशन बॉन्ड शुरू किया गया है, जिसमें इन्हें नोटिस जारी हो रहे हैं। बीर लचित सेना, जातीय संग्रामी सेना, अखिल असम अनुसूचित जाति छात्र संस्था, ताई आहोम चरत्र समेत 27 संस्था प्रतिनिधियों को नोटिस मिल चुके हैं।

30 जातीय संगठनों ने एक मुस्लिम कांग्रेसी विधायक अब्दुल रशीद मंडल के शिवसागर जिले में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। संगठन सीएम के उस बयान के बाद सड़कों पर उतर आया है जिसमें सीएम सरमा ने कहा था कि असम में लोकसभा चुनाव के बाद जिन क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, वहां एक विशेष समुदाय को इतना साहस मिला कि वह अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और महिलाओं पर अत्याचार इसी का परिणाम है।

आईएमए ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित की

नई दिल्ली (ईएमएस)। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी है। यह कदम इस महीने की शुरुआत में कोलकाता स्थित इस संस्थान में एक जूनियर डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की सीबीआई जांच के बीच उठाया गया है।

आईएमए ने एक आदेश में कहा कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आर.

जन हितैषी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बढ़ेगी भारत में बेरोजगारी

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। विभिन्न उद्योग, मार्केटिंग, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भविष्य में आने वाले हैं। लगभग 10 फ़ीसदी इसका प्रभाव वर्तमान में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोग की पहचान, दवाइयां और इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी, मरीज की देखरेख एआई के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवाएं जल्द शुरू होगी। एआई के माध्यम से टेली मेडिसिन, रिमोट सर्जरी के भी नए आयाम शुरू होंगे। इसमें डॉक्टर नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं उसमें तकनीकि के माध्यम से बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। अभी जो कमी बनी हुई है, उसे आसानी से पूरा किया जा सकेगा। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। एआई तकनीकी के माध्यम से फसल की उपज, मौसम की भविष्यवाणी, फसलों में लगने वाले कीट और उनका उपचार फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कृषि विज्ञान के छात्रों को पढ़ाई में इससे मदद मिलेगी। डेटा उपलब्धता और विविधता के कारण चैट वाटस और वर्चुअल असिस्टेंट में ग्राहकों की सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। रक्षा के क्षेत्र में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होना शुरू हो गया है। इस तकनीकी के उपयोग से नैतिक और कानूनी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। जिन पर विशेष सतर्कता की जरूरत होगी। एआई तकनीकी के माध्यम से मानव हस्तक्षेप कम होगा। स्वचालित प्रणाली का विकास होगा। ड्रोन और मानव रहित वहां एआई तकनीकी के माध्यम से सैकड़ों संचालित होंगी। एआई तकनीकी का साइबर सुरक्षा में बड़े पैमाने पर उपयोग होगा। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में इस तकनीकी के कारण कई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी इस तकनीकी को जानना जरूरी होगा। एआई तकनीकी के माध्यम से सिस्टम स्वयं निर्णय लेता है। जिसके कारण मानव उपयोग कम होगा। रोबोट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के संचालित होने से बेरोजगारी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसका असर लॉजिस्टिक और सप्लाई के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होगा। छात्र-छात्राओं को मनवांछित जानकारी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होगी। परिवहन के क्षेत्र में भी इसी तकनीकी का उपयोग बड़े पैमाने पर होगा। सरकारी नीतियों, प्रशासन और व्यापारिक संगठनों द्वारा भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर एआई तकनीकी भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत होगी। रोजगार के क्षेत्र में अब एआई तकनीकी के जानकारों का बोलवाला होगा। पांच दशक पहले जैसे टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक था। तीन दशक पहले कंप्यूटर का ज्ञान बहुत आवश्यक होता था। अब कंप्यूटर के साथ-साथ एआई तकनीकी को जानना बहुत जरूरी होगा। इसी से रोजगार के अवसर मिलेंगे। एआई की जो नई क्रांति आई है। उसको नजर अंदाज करना अब संभव नहीं होगा। सुव्यवस्थित रूप से इसका इसका उपयोग करने पर भविष्य में बेहतर परिणाम नौकरी, व्यापार, सेवा, उत्पादन इत्यादि के क्षेत्र में होगा। इसके बिना प्रगति संभव नहीं होगी। परिवार, समाज, संगठन और सरकारों को भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस बदलाव पर काम करना होगा। एआई तकनीकी के माध्यम से सारी दुनिया के विविधता की जानकारी विभिन्न भाषाओं में कहीं पर प्राप्त की जा सकती है। जिस रूप में और जैसा आप चाहते है, एआई तकनीकी के माध्यम से वह तुरन्त उपलब्ध होती है। जिसके कारण एआई तकनीकी पर दिनों-दिन डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से इसके परिणाम वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है, भारत जैसे देश में मिडिल की पढ़ाई के साथ में एआई तकनीकी का कोर्स कराने की जरूरत होगी। भविष्य में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा दुनिया के देशों में देखने को मिल रही है। विविधता के साथ विभिन्न विषयों का ज्ञान एक स्थान पर एकत्रित हो चुका है। उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, यह बाजारवाद के सिद्धांत पर आधारित होगी। अर्थात मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस तकनीकी के माध्यम से सभी कार्य बेहतर ढंग से बहुत कम समय में कराए जा सकेंगे। इसके लिए दक्ष मानव उपयोग जरूरी होगा। रोबोट एवं अन्य मशीनीकृत व्यवस्था एआई तकनीकी के माध्यम से अधिकांश काम होंगे। जिसके कारण दुनिया के देशों में बेरोजगारी बढ़ने का भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तकनीकि एवं संचार माध्यमों में जो परिवर्तन आ रहे हैं। उससे सभी को सजग होने की जरूरत है।

जम्मू-कश्मीर चुनाव से नये दौर की उम्मीद

जम्मू एवं कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा निश्चित ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती देने के साथ क्षेत्र के लिए विकास के नए दौर के द्वार खोलने का माध्यम बनेगी। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 43 जम्मू और 47 कश्मीर की सीटें हैं, इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर ऐसी सरकार बनाये जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान चुनावी सरगर्मियों एवं भविष्य के गर्भ में ईवीएम से निकलने वाले जनादेश पर लगी हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। इस बार के चुनाव अब तक हुए चुनावों से अलग है और खास है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामाकंन भरने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन तमाम बड़ी पार्टियों के बीच असमंजस और अनिश्चितता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ हद तक इस तरह की अनिश्चितता हर चुनाव में होती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के मामले में हालात सामान्य से ज्यादा जटिल हैं और इस असमंजस के पीछे उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी खेमे में माने जाने वाले राज्य के तीनों प्रमुख दलों में सहयोग और संघर्ष दोनों का दिलचस्प घालमेल दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सभी 90 सीटों पर गठबंधन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आलम यह है कि पहले चरण की 24 सीटों का भी बंटवारा मुश्किल साबित हो रहा। पीडीपी इस गठबंधन से बाहर है। फिर भी मुद्दों की एकरूपता के चलते न सिर्फ उमर अब्दुल्ला उससे अपनी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी न खड़ा करने को कह रहे हैं बल्कि खुद महबूबा भी कह चुकी हैं कि अगर उनके अजेंडे को स्वीकार किया गया तो गठबंधन का समर्थन करेंगी। भाजपा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में नहीं है, इसलिए वहां इस तरह की गफलत नहीं है, लेकिन निर्णय लेना और उसे लागू करना वहां भी जटिल बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर उसे जिस तरह वापस लेना पड़ा, उससे उसकी छिछालेदार तो हुई ही है, अनुशासित दल की उसकी छवि को धक्का भी लगा। स्थिति यह है कि पार्टी ने सोमवार को 44 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के थोड़ी ही देर बाद व्यापक विरोध के कारण उसे वापस ले लिया। इसके बाद जो सूची जारी की गई, उसमें 15 ही प्रत्याशियों के नाम थे। यह आलम तब है, जब पहली सूची भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूर की गई थी।

यदि भाजपा औरों से अलग तथा अनुशासित दल की अपनी छवि के प्रति सचेत है तो उसे प्रत्याशी चयन की अपनी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक आकार देना ही होगा। पहले जारी सूची का विरोध जिन कारणों से हुआ, उनमें एक तो दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बनाना रहा और दूसरे दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों का नाम न होना। लगता है भाजपा को अभी भी लोकसभा चुनावों में हुई गलतियों का आभास नहीं है। लोकसभा चुनाव में उसे दूसरे दलों के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का किस तरह नुकसान उठाना पड़ा था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची का विरोध यह भी बताता है कि भाजपा प्रत्याशी चयन की कोई नीर-क्षीर, पारदर्शी और ऐसी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकी है, जिससे असंतोष, विरोध और भितरघात का सामना न करना पड़े। वैसे यह समस्या केवल भाजपा की ही नहीं, सभी दलों की है। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दें। यह कठिन कार्य नहीं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र विकसित करने से बच रहे हैं।

चुनाव अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं। सब राजनैतिक दल अपने-अपने 'घोषणा-पत्र' को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बताकर सब समस्याएं मिटा देने तथा सब रोगों की दवा बन जाने की नैतिकता की बातें करते हुए व्यवहार में अनैतिकता को छिपायेंगे। टुकड़े-टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक होंगे। सत्ता तक पहुँचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण व आवश्यकता बतायेंगे। इस बार दलों में जितना अन्दर-बाहर होता हुआ दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव परिणामों के बाद भी एक बड़ा दौर असमंजस का चलेगा। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि ''अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे।'' इसलिये प्रांत के लोगों को मतदान करते हुए विवेक का परिचय देना होगा।

इन चुनावों की जटिलता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि एक दशक पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लैस जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य के दर्जे से भी वंचित है। उस चुनाव में दो सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां पीडीपी और भाजपा एक-दूसरे की धुर विरोधी हो चुकी हैं। राज्य में अब भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिन्दू बहुल सीटों और कश्मीरी पंडितों के वोट बैंक को अपने खाते में डालने के इरादे से मैदान में उतर रही है और ऐसे में कांग्रेस की हालत खराब होना तय माना जा रहा है। भले ही सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया है, लेकिन भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए भविष्य में क्षेत्रीय दलों के भाजपा के साथ बहती हवा में जाने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है, इस दृष्टि से वहां होने वाले चुनाव भी विशेष एवं अन्य राज्यों से भिन्न है। बड़ी बात यह है कि पार्टियां एक-दूसरे के बारे में चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। निश्चित ही इन चुनाव परिणामों से उम्मीद जगी है कि यहां से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही इन चुनावों की सार्थकता है।

जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेगी। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड लाख पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। चुनाव घोषित हो जाने से तथा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से जो क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसने ही सबके दिमागों में सोच की एक तेजी ला दी है। प्रत्याशियों के चयन व मतदाताओं को रिझाने के कार्य में तेजी आती जायेगी। परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम राज्य का वातावरण चुनावों के अनुकूल बने। राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। पुराने चेहरों पर उसका विश्वास नहीं रहा। अब प्रत्याशियों का चयन कुछ उसूलों के आधार पर होना चाहिए न कि जाति और जीतने की निश्चितता के आधार पर। मतदाता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ की परिपक्वता दिखाई दे रही है। ये चुनाव ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब राज्य लम्बे दौर की विभिन्न चुनौतियों से जूझने के बाद शांति एवं विकास की राह पर अग्रसर है।

(लेखक-ललित गर्ग/ईएमएस)

कर्मो से भाग्य बदल जाता है

जीवन का एक नियम है कि अगर तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी हो जाती हैं। आधुनिक मानव रातों रात सफल होना चाहता है सब्र नहीं करता संघर्ष नहीं करता और असफल हो जाता है। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है इतिहास साक्षी है की दुनिया में सफल लोगों ने बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल किया है। मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए राह में कई मोड़ आते हैं आधीयां तूफान आते हैं ऐसे तूफानों का सामना करना चाहिए क्यूंकि तूफान थम जाता है हौसला रखना चाहिए डरना नहीं चाहिए डर के आगे जीत होती है। समय पर हर इच्छा पूरी हो जाती है। भाग्य को कर्मो से बदला जा सकता है अतीत बदल जाता है सच्चे मन कर्म करना पड़ता है बाधाओं को पार करना पड़ता है खून पसीना बहाना पड़ता है। भाग्य बदल जाता है हर दरवाज़े खुल जाते है सफलता की कुंजी मिल जाती है। असफलता भी बहुत कुछ शिक्षा देती है अथक मेहनत से सफलता मिल जाती है। समय के महत्व को समझें और अपनी महत्वकाक्षांओं को पूरा करें। समय के पाबंद बने। अगर समय के साथ नहीं चलोगें तो पिछड़ जाओगें। समय का प्रबंधन करें। समय सारणी बनाएं और हर पल का फायदा उठाएं। समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय एक अनमोल पूंजी है। समय को जिसने भी बरबाद किया समय ने उसे भी बरबाद कर दिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का सदुपयोग करोगे तो सफलता हासिल करोगे अगर समय का दुरुपयोग किया तो धराशायी हो जाओगे। वक्त का पहिया जब घूमता है तो कंगाल होने में देर नहीं लगती। मानव को हमेशा अतीत का आईना देखते रहना चाहिए ताकि अहसास होता रहे कि ऐसे भी दिन थे दिन एक जून की रोटी नसीब नहीं होती थी आज जब समय बदला तो अपना गुजरा हुआ वक्त भूल रहा है। आदमी भले ही कितना बड़ा बन जाए अतीत की परछाईयां उसका दामन नहीं छोड़ती मरते दम तक साथ रहती हैं। । वक्त बदलते देर नहीं लगती भाग्य किसी को भी अर्श पर ले जाता है और किसी को फर्श पर ले जाता है इसलिए मानव को मर्यादा में रहकर ही हर काम करना चाहिए। आदमी को किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता तो फिर से कायम कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मानव का जीवन व्यर्थ है जो दूसरों को दुख देता है। समय के पास सबका लेखाजोखा है। मानव को समय से डरना चाहिए न जाने कब कैसा समय देखना पड़े। समय का मिजाज पता नहीं कब बदल जाए। समय ने बड़े से बड़े तानाशाहों को धूल चटा दी जो समय के खिलाफ चले थे मिटटी में मिल गए। आज मानव के पास अच्छा करने का समय ही नहीं है जबकि बुरा करने के लिए समय ही समय है। मानव कितन भी अमीर हो जाए अपना गुजरा हुआ समय नहीं खरीद सकता। आज लोग मोबाईल फोन पर समय बरबाद कर रहे है। चौबीसों घंटे सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते है। समय की जिसने कदर की समय ने उसे उचाईयां दी है। मानव को चाहिए कि समय के हर एक मिनट और सैकंड व घंटों का सही सदुपयोग करे। जो समय के साथ निर्बाध गति से चला समय ने उसे मंजिल तक पहुंचाया है। समय से डरो अच्छे कर्म करो। जीवन में हम अनेक सुख-दुख देखते है,परन्तु क्या हमने किसी और के लिए कुछ करने के बाद सच्चे सुख की अनुभूति की है दूसरों को अपनी सामथ्र्य के अनुसार दीजिए ,खासकर उन्हे जो अनेक चीजों से वंचित ही रहे या जिन्हे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। आप महसूस करेगें कि परोपकार का काम करने के बाद आपके होंठों पर आई मुस्कराहट दुनियाभर की दौलत से भी मंहगी होगी। समय मानव को कई रंग दिखाता है। समय मानव की परीक्षा लेता रहता है। समय का सही मायने में सम्मान करो। समय अनमोल है व दुर्लभ है। सुख में तो सभी साथ होते है मगर दुख में साथ छोड देते है, आदमी आज गिरगिटों की तरह रंग बदलता है। आज मानव मतलब निकल जाने पर पहचानने से इन्कार कर देता है। आज मानव ने भले ही कितनी प्रगति कर ली है मगर सोच वही सामंतवादी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मगर आज रिश्ते तराजू पर तोले जाते है अगर कोई गरीब है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। वक्त बदलते देर नही लगती इसलिए आदमी को अपना अतीत याद करते रहना चाहिए। ताकि विपतीयो का अहसास होता रहेआदमी को सादगी व उच्च विचारों मे विश्वास रखना चाहिए। समय यही सिखाता है कि किसी का समय बरबाद मत करो। समय कीमती है जिसने समय की कीमत जान ली है वह हर जगह सफल होता है। आज अच्छाई के लिए समय नहीं है। बुराई के लिए हर समय तैयार है। समय एक जैसा नहीं रहता आज अच्छा है कल का पता नहीं कैसा होगा। समय को पहचानो तभी समय आपको एक अलग पहचान देगा। समय रेत की तरह हर पल फिसल रहा है समय को बांधा नहीं जा सकता यह अटल सत्य है। समय बहुत ही बलवान है वक्त के थपेडों से कोई नहीं बच पाया है। समय से डरो, समय बदलता रहता है। (लेखक-नरेंद्र भारती/ईएमएस)

बलात्कार , बंद और बीजेपी

आज का शीर्षक किसी आने वाली फिल्म का नाम नहीं है। ये शीर्षक भारतीय राजनीति में बलात्कार को लेकर राजनीतिक दलों के चरित्र को उजागर करती एक लघुकथा का नाम है। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ ज्यादती के बादकी नृशंस वारदात के बाद बंगाल में भाजपा की राजनीति इतनी बढ़ गयी है कि अब मामला बंगाल बंद तक आ पहुंचा है । इससे पहले आरक्षण के मामले पर विभिन्न संगठनों ने भारत बंद किया था। यानि राजनीति में अब यदि आरक्षण की बात करना है तो आपको बंद करना होगा और यदि महिला उत्पीड़न की बात करना है तो आपको बंद का इस्तेमाल करना होगा। प्रतिकार के लिए शायद बंद के आव्हान से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है।

ऐसी लोक-मान्यता है कि यदि देश ,सूबा या कोई शहर बंद किया जाता है तो सत्ता प्रतिष्ठान के कान खुल जाते हैं ,आँखें खुल जाती हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि ये धारणा उचित नहीं है । सत्ता प्रतिष्ठान को नींद से जगाने के लिए अब बंद कारगर हथियार नहीं रह गया है। फिर भी बंद का आव्हान किया जाता है। बीजेपी ने बंगाल बंद का आव्हान किया तो कम से कम मुझे तो हैरानी हुई ,क्योंकि महिला उत्पीड़न अब केवल बंगाल की समस्या नहीं है। पूरे देश की समस्या है। इसलिए यदि बीजेपी को बलात्कार या क़ानून और व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बंद का आव्हान करना था तो उसे भारत बंद का आव्हान करना था ,क्योंकि बलात्कार केवल कोलकाता में ही नहीं हुआ। बलात्कार बीजेपी शासित राजस्थान में भी हुआ है,महाराष्ट्र के बदलापुर में भी हुआ है और मध्यप्रदेश के ग्वालियर में भी।

बलात्कार कम से कम भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है। एनसीआरबी के आंकड़े ही सही मान लिए जाएँ तो इस देश में हर साल कम से कम 25 हजार महिलायें बलात्कार का शिकार होतीं है। ये तो वे महिलाएं हैं जो साहस कर पुलिस में रिपोर्ट करने पहुंचतीं हैं,बाकी इससे ज्यादा बलात्कार के मामले लोक - लाज,भय और असुरक्षा की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते। बलात्कार के मामलों को फास्ट कोर्ट में चलाने और आरोपियों की सजा दिलाने में हमारी सरकारें नाकाम रहीं है। अभियोजन अक्षम साबित हुया है। कुल 27 फीसदी मामलों में ही आरोपियों को सजा मिली है। हमारी अदालतें तो बलात्कार के मामलों में सजायाफ्ता अपराधियों को फलरो के तहत बार-बार जमानत देने कि उदारता और दिखा रहीं है।

बलात्कार के बहाने से बीजेपी ने एक काम जरूर किया है कि यदि बलात्कार का आरोपी है तो उसके घरों को बुलडोज जरूर कर दिया है । बीजेपी का ये पुरुषार्थ भी विवादों की एक बड़ी वजह है । लेकिन बीजेपी भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों को दण्डित करने के बजाय बुल्डोजर संहिता पर ज्यादा भरोसा करती है। बलात्कार के मामलों को लेकर हमारी देश की अदलातों का व्यवहार भी सिलेक्टिव्ह जान पड़ता है। हमारी अदालतें कोलकाता के बलात्कार के मामले में सीबीआई को हड़काती है ,लेकिन ऐसा कितने मामलो में होता है। क्या सीबीआई हर मामले की जांच करने के लिए तैयार है ? क्या भाजपा द्वारा नियुक्त तमाम राज्यपाल बलात्कार पीड़ितों के परिजनों से उसी तरह मिलने के लिए राजी हैं जैसा की वे कोलकाता में कर रहे है ?

बलात्कार के नाम पर बंद की राजनीति ही नहीं बल्कि राज्यपालों की राजनीती भी बंद होना चाहिए । भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां बलात्कार नहीं होते । जहाँ कोलकाता से ज्यादा जघन्य वारदातें नहीं होतीं ? बलात्कार एक सामाजिक विकृति का मुद्दा है। क़ानून और व्यवस्था का मुद्दा है ,राजनीति का मुद्दा नहीं। यदि बलात्कार के मुद्दे पर बीजेपी राजनीति करती है तो भी बुरी बात है और यदि कांग्रेस करती है तो भी बुरी बात है। बुरी बात तो बुरी बात ही है ,चाहे फिर कोई भी राजनीतिक दल हो। राजनीति का मुकाबला राजनीति से हो ,कार्यक्रमों से हो ,नीतियों से हो न की मुकाबला करने के लिए बलात्कार जैसी घृणित वारदात का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाये।

बंगाल जीतना बीजेपी का एक पुराना सपना है ,लेकिन दस साल केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी बंगाल नहीं जीत पायी है। साम,दाम,दंड और भेद से भी नहीं जीत पायी। राज्यपालों के दुरूपयोग से भी नहीं जीत पायी। अब बंगाल में बार-बार खेत होती रही बीजेपी बलात्कार के मुद्दे पर बंद का आयोजन कर बंगाल को जीतना चाहती है। लेकिन बंगाल को जीतना यदि इतना ही आसान होता तो महाबली अमितशाह वहां परास्त न होते। बंगाल जीतने का सपना पूरा न होने से बीजेपी हताश है और हताशा में ही बीजेपी घृणित राजनीति पर उतर आयी है। बीजेपी का दर्द इसलिए और ज्यादा है कि उसे बंगाल में बार-बार एक महिला मुख्यमंत्री से पराजित होना पड़ रहा है।

बीजेपी को महिलाएं नेतृत्व करती अच्छी नहीं लगतीं ,भले ही बीजेपी की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित कराया हो। बीजेपी ने स्वर्ग जा चुकी श्रीमती सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया । उमा भारती को घर बैठा दिया । मायावती को कहीं का नहीं छोड़ा। मेहबूबा मुफ़्ती का मुख्यमंत्री बने रहना बीजेपी को पसंद नहीं आया । कांग्रेस की चेयर पर्सन रही श्रीमती सोनिया गाँधी तक को जर्सी गाय कहकर अपने महिला विरोधी चरित्र का मुजाहिरा किया है। बंगाल में बीजेपी जीते ,जरूर जीते लेकिन किसी महिला के उत्पीड़न को औजार बनाकर नही। बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में लड़ रही है ,जरा दक्षिण के राज्यों में भी लड़कर दिखाए। लेकिन ये हो नहीं सकता ,क्योंकि बीजेपी आखिर बीजेपी है।

आपका पता नहीं ,लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय के दर्द से अभी तक उबरी नहीं है ।। जबकि उसे अपनी पराजय के दर्द को भुला देना चाहिए ,क्योंकि अंततोगत्वा देश में सत्ता के शीर्ष पर भाजपा ही है ,भले ही उसकी मांग में जेडीयू और टीडीपी से उधार लिया हुआ सिन्दूर भरा हुआ है ,लेकिन है तो बीजेपी सौभाग्यवती राजनितिक पार्टी। अब ये उसके नेतृत्व के ऊपर है कि वो हिकमत अमली से अपनी लूली-लंगड़ी सरकार पूरे पांच साल चलाना चाहती है या बीच में ही रणछोड़ बनना चाहती है। बीजेपी को अब ये हकीकत स्वीकार कर लेना चाहिए कि भविष्य में वो 2014 या 2109 का इतिहास तो नहीं दोहरा सकती।बीजेपी को जितना आसमान छूना था ,सो छू चुकी है। अब कहीं की ईंट और कहीं के रोड से बीजेपी का किला महफूज रहने वाला नहीं है। फिर चाहे रोड का नाम चम्पाई सोरेन हो या नीतीश कुमार।(लेखक-राकेश अचल/ईएमएस)

हरमनप्रीत को टी20 विश्वकप जीतने का भरोसा

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि इस बार उनकी टीम का लक्ष्य टी20 विश्वकप जीतना रहेगा। टी20 विश्वकप अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेला जाएगा। हरमनप्रीत का मानना है कि यूएई के हालात उनकी टीम के लिए लाभप्रद रहेंगे। हरमनप्रीत ने कहा, 'जब भी हम विश्व कप जैसे किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं तो हमारा लक्ष्य बेहमतर प्रदर्शन करना रहता है। साथ ही कहा कि हमने पूर्व में भी हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम अंतिम बाधा को पार करने में सफल रहेंगे और खिताबी जीत हासिल करेंगे। हरमनप्रीत ने कहा कि टूर्नामेंट के आयोजन स्थल में बदलाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यूएई के मैदान भारत के जैसे ही हैं।

उन्होंने कहा, 'हमने यूएई में काफी क्रिकेट नहीं खेला है पर यूएई की परिस्थितियों हमारे यहां के समान ही नजर आती हैं। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम 2020 टी20 विश्व कप के फाइनल में हार गयी थी पर इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहतीं। उन्होंने कहा, 'हम देखेंगे कि वहां के हालात कैसे होते हैं, हम जितनी जल्द हो हालात से तालमेल बैठाने के पूरे प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि हालात चाहे जैसे भी हों टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, 'एक टीम के रूप में, हम अपनी असफलताओं से ही सीखते हैं और उन बाधाओं को तोड़ते हैं जो हमें पीछे करती रही हैं। उम्मीद है कि इस बार हम विश्व कप में और अधिक सकारात्मक तरीके से खेलेंगे।

शब्द पहेली - 8112

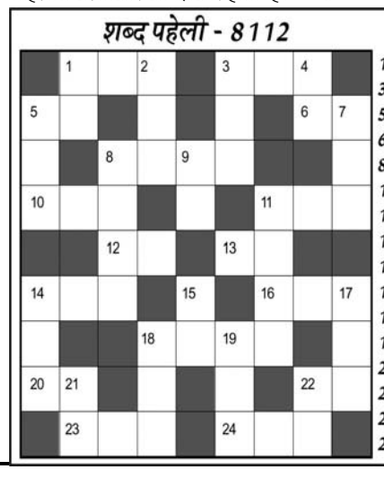

बाएँ से दाएँ

1.सरस्वती-3
3.किनारा,तट-3
5.मूल्य,कीमत-2
6.उस समय-2
8.प्रबंध,व्यवस्था-4
10.नमक-3
11.अधीन,मातहत-3
12.संज्ञा,संबोधन-2
13.मार्ग,रास्ता-2
14.तीर्थ,धार्मिक यात्रा-3
16.धुन,आसक्ति-3
18.जमानत-4
20.रहस्य-2
22.पुत्र,तनय-2
23.मुलायम-3
24.गंवार,अनपढ़-3

ऊपर से नीचे

1.संध्या,सांझ-2
2.असुर,दैत्य-3
3.शोरबा,रसा-3
4.बुरी आदत-2
5.प्रवेश,एडमिट-3
7.वर यात्रा,दूल्हे का जुलूस-3
8.प्रियतम,साजन-4
9.अनाज-2
11.सनसनी,रोमांच-4
14.तृतीय-3
15.सच्चाई,सत्य-2
17.जिसकी नाक कटी हो, वादा फरामोश-3
18.मुंशी,दीवान-3
19.रवैया,तरीका-3
21.आम जनता-2
22.लता,लतिका-2

शब्द पहेली -8111 का हल

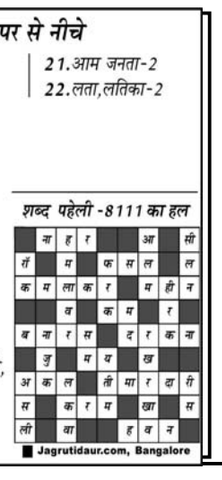

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

जय शाह से पहले ये चार भारतीय भी बने थे आईसीसी प्रमुख

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नये चेयरमैन बनाये गये हैं। 35 साल के जय शाह दिसंबर में ये पद संभालेंगे। इस प्रकार वह इस पद पर बैठने वाले सबसे कम उम्र के आईसीसी प्रमुख होंगे। गत दिवस ही उन्हें आम राय से आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया वह आईसीसी प्रमुख बनने वाले पांचवें भारतीय होंगे। इससे पहले भारत के ही जगमोहन डालमिया, शरद पवार , एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर भी आईसीसी प्रमुख रहे हैं।

जगमोहन डालमिया : आईसीसी प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय थे। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को साल 1997 में आईसीसी अध्यक्ष चुना गया था। वह तीन साल तक इस पद पर बने रहे। डालमिया आईसीसी की कमान संभालने वाले पहले एशियाई थे। उनके समय ही बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा मिला था।

शरद पवार : आईसीसी चेयरमैन बनने वाले दूसरे भारतीय शरद पवार थे। साल 2010 में उन्होंने ये पद संभाला था।

एन श्रीनिवासन : बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन आईसीसी प्रमुख बनने वाले तीसरे भारतीय रहे हैं। जून 2014 को उन्हें ये पद संभाला था। उनको एक साल बाद ही साल 2015 में पद छोड़ना पड़ा था।

शशांक मनोहर : वहीं आईसीसी में सबसे लंबे समय तक काम करने वाले भारतीय शशांक मनोहर रहे हैं। नवंबर 2015 में उनको श्रीनिवासन की जगह चेयरमैन बनाया गया था। वह 30 जून 2020 तक इस पद

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ। दुनिया भर से मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीददारी हावी होने से बाजार ऊपर आया है। आज कारोबार के दौरान आईटी और फार्मा क्षेत्र में तेजी आई। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 73.80 अंकों की बढ़त के साथ ही 81,785.56 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 34.60 अंकों की तेजी के साथ ही 25,052.35 के लेवल पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान

निफ्टी मिडकैप में 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ ही व्यापक सूचकांक भी निचले स्तर पर बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स में भी आज कुछ ही क्षेत्रों में बढ़ती रही। सबसे ज्यादा उछाल निफ्टी आईटी में1.66 फीसदी की रही। निफ्टी फार्मा सेक्टर में भी 1.21 फीसदी का उछाल आया। बाजार जानकारों के अनुसार निफ्टी में बढ़त विदेशी निवेशकों के शुद्ध खरीदार बने रहने और अगले महीने अमेरिकी फेड की तरफ से नीतिगत ब्याज दरों में कमी की उम्मीद से आई है। आज कारोबार के दौरान निफ्टी के जिन शेयरों में आज सबसे ज्यादा उछाल रहा वे हैं एलटीआई माइंडट्री। इसके शेयर 6.31 फीसदी बढ़कर 6,114.60 रुपये पर बंद हुए। इसके अलावा, विप्रो डिविज लैब , भारती एयरटेल और इंफोसिस के शेयर शीर्ष पर रहे। इसमें 3.71 फीसदी, 2.71 फीसदी, 2.05 फीसदी और 1.99 फीसदी की तेजी रही।

निफ्टी मीडिया में आज सबसे ज्यादा 1.41 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में सबसे ऊपर मारुति सुजूकी के शेयर रहे। इनमें 1.34 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी। इसके अलावा, एशियन पेंट्स, अदाणी एंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस और ब्रिटानिया के शेयर भी गिरे हैं।

इससे पहले आज सुबह बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला। शुरुआत में ही सेंसेक्स 74.59 अंक करीब 0.09 फीसदी बढ़कर 81,786.35 अंक पर जबकि निफ्टी 19.50 अंक तकरीबन 0.08 फीसदी ऊपर आकर 25,037.30 अंक पर कामकाज कर रहा था। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स करीब 20 अंक नीचे आकर 24,998 पर कारोबार कर रहा था जिससे अंदाजा होता है कि बाजार में नकारात्मक माहौल है।

वहीं एशियाई बाजार में गिरावट रही। ऑस्ट्रेलिया के मुद्रास्फीति डेटा से पहले एएसएक्स 200 0.47 फीसदी नीचे आया। निक्केई में 0.21 फीसदी और कोस्पी में 0.27 फीसदी की गिरावट रही। फेड चेयर जेरोम पॉवेल के इस बयान के बाद किकेंद्रीयबैंक नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के लिए तैयार है।बाजारों को मौद्रिक नीति में शीघ्र ही बदलाव होने की उम्मीद है। गत दिवस अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान एसएं डपी 500 0.16 फीसदी बढ़ा,जबकि डॉव जोन्स 0.02 फीसदी और नैस्डैक 0.16 फीसदी बढ़ा। वहीं गत कारोबारी में भी बाजार में सपाट कारोबार हुआ था। बाजार जानकारों का कहना है कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण एफआईआई (विदेशी निवेशक) खरीददार बन गए हैं।

सूडान में बारिश और बाढ़ से 138 लोगों की मौत

खार्तूम (ईएमएस)। सूडान में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 138 हो गई है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 10 राज्यों में भारी बारिश के कारण 138 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय ने कहा, बारिश के कारण कुल 138मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 31,666 परिवारबाढ़सेप्रभावितहुएहैं।इसमें 12 9,650 से अधिक लोग शामिल हैं। इसके अलावा12,420 घर पूरी तरह से ढह गए हैं। इतना ही नहीं बारिश और बाढ़ से प्रभावित सूडान के पांच राज्यों में हैजा के 102नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पांच लोगों की मौत भी हुई है। यहां सक्रिय मामले1,223हैं आठ लोगों की मौत हुई है।

सूडान में बाढ़ एक प्रमुख समस्या है। यहां जून और अक्टूबर के बीच बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ है और कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। इस साल बारिश के मौसम ने सूडान में मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है, जो पहले से ही सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच घातक संघर्ष से जूझ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार,सूडान में लगभग 10.7 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, जिसमें लगभग 2.2 मिलियन लोग विदेशों में शरण ले रहे हैं। शनिवार को काफी मात्रा में बारिश होने से लाल सागर के तट पर स्थित पोर्ट सूडान के उत्तर में अरबत क्षेत्र में बाढ़ आ गई। जलस्तर बढ़ने से अरबत बांध टूट गया और कई गांव बह गए हैं। इस बांध का निर्माण 2003 में किया गया था। ताकि सूखे की समस्या से निजात मिल सके।लेकिन, बीते कई सालों से इस बांध का रखरखाव नहीं किया गया है।

एकीकृत पेंशन योजना राज्यों के लिए जरुरी नहीं, ले सकते हैं स्वतंत्र निर्णय -वित्तमंत्री सीतारमण

नई दिल्ली,(ईएमएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) राज्यों के लिए जरुरी नहीं है। राज्य स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। वित्तमंत्री ने उम्मीद जताई कि ज्यादातर राज्य यूपीएस को लागू करेंगे क्योंकि इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत दिए गए लाभ हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सुधार करने का प्रयास है। यूपीएस पेंशन की गारंटी लागू करना किसी निर्णय को वापस लेना यू-टर्न नहीं है। यह एक नया पैकेज है। केंद्र सरकार यूपीएस लाने की घोषणा के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने पहले इसे रोलबैक सरकार कहते हुए चुटकी ली थी। वित्तमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नारेबाजी करने वाली पार्टी बन गई है।

9 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक के एजेंडे पर चर्चा करते हुए सीतारमण ने कहा कि इसमें जीएसटी दरों को वाजिब बनाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का समूह रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और बैठकें करेगा। यूपीएस उन समस्याओं का समाधान करेगा जो पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों की सेवा 25 साल से कम है तो यूपीएस के तहत लाभ आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यूपीएस के कोष की जिम्मेदारी संभालेगा। वित्तमंत्री ने साफ किया कि यूपीएस के लिए कर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े लाभ देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने बीते शनिवार को यूपीएस को मंजूरी दी थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी और केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के मुताबिक यूपीएस में बकाया भुगतान के मद में 800 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और पहले साल इस योजना पर करीब 6,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

ऐसा क्या हुआ.....जापान में लोग कर रहे चावल की बंपर खरीद

स्टॉक हुआ खत्म, सरकार हुई चिंतित

टॉक्यो (ईएमएस)। जापान दुनिया के सबसे विकसित देश में शामिल है। हालांकि इन दिनों जापान में एक संकट आ गया है। दरअसल जापान में लोगों ने महाभूकंप और कई तूफानों के खतरे के साथ-साथ एक हफ़्ते की छुट्टी के कारण घबराहट में खरीदारी की है। इस खरीदारी के कारण देश के सबसे मशहूर खाद्य पदार्थों में से एक चावल की अभूतपूर्व कमी हो गई है। इसके बाद जापान सरकार ने लोगों को घबराहट में खरीदारी न करने की चेतावनी दी।

टोक्यो में लोकप्रिय सुपरमार्केट चेन की एक शाखा के क्लर्क के हवाले से बताया गया कि हम इस गर्मी में चावल की सामान्य मात्रा का आधा ही खरीद पाए और चावल के बैग जल्दी ही बिक गए। कर्मचारी ने बताया कि चावल का दैनिक स्टॉक आमतौर पर दोपहर तक खत्म हो जाता है।

इस महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा संभावित महाभूकंप और कई तूफानों की चेतावनी दिए जाने के बाद लोगों ने अपने घरों में चावल का राशन बनाना शुरू कर दिया। जापान में दुकानों में चावल खत्म होने या चावल की कमी का सामना करने का एक और कारण ओबोन की छुट्टी है। इसके अलावा, गर्म मौसम और पानी की कमी के कारण कम फसल के साथ-साथ रिकॉर्ड संख्या में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती मांग के कारण भी चावल की कमी हुई।

टोक्यो में एक किराने की दुकान पर लगे साइनबोर्ड पर लिखा था, अधिक से अधिक ग्राहकों को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए, हम आपसे प्रति परिवार प्रतिदिन एक (चावल का बैग) खरीदने के लिए कहते हैं। जापानी सरकार ने लोगों को चावल की खरीददारी में हड़बड़ी न करने की चेतावनी दी। कृषि मंत्री तेत्सुशी सकामोटो ने लोगों को शांत रहने की सलाह देकर कहा कि कमी की स्थिति जल्द ही हल होगी। देश में जून में चावल का सबसे कम स्टॉक 1999 के बाद से देखा गया, जब तुलनात्मक डेटा पहली बार एकत्र किया गया था। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि स्टॉक पर्याप्त है। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, सितंबर के अंत तक 40 प्रतिशत फसल उपलब्ध होने के साथ एक नया कटाई का मौसम शुरू हो गया है।

भारत में आईटी कंपनियों से ज्यादा वेतन दे रही जीसीसीएस

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसीएस) के विस्तार और टेक पेशेवरों की बढ़ती मांग के कारण, आईटी सेवाओं वाली कंपनियों की तुलना में वेतन अंतर बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट बताती है कि जीसीसीएस समान टेक पोजिशन के लिए आईटी सेवाओं और अन्य नॉन-टेक उद्योगों की तुलना में 12-20 प्रतिशत तक ज्यादा वेतन दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, जीसीसीएस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उनके अनुभव के आधार पर सालाना 9.7 लाख से लेकर 43 लाख रुपये तक का वेतन दे रहे हैं। इसके विपरीत, आईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेक्टर में एंट्री-लेवल पदों के लिए करीब 5.7 लाख रुपये प्रति वर्ष का वेतन दिया जाता है, जो आठ साल से अधिक अनुभव रखने वालों के लिए 17.9 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंचता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में भारत में संचालित 1,600 जीसीसीएस में 16.6 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। अगले पांच से छह सालों में अतिरिक्त 800 जीसीसीएस स्थापित होने की उम्मीद है, जिससे भारत का ग्लोबल टेक हब के रूप में महत्व और बढ़ेगा। इन नए जीसीसीएस में से कई कोलकाता, अहमदाबाद और वडोदरा जैसे टियर-2 शहरों में स्थापित होने की संभावना है, जिससे भौगोलिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। वित्तीय साल 24 में, भारत का टेक्नोलॉजी मार्केट 254 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि है। इस बाजार को 5.6 मिलियन की टेक वर्कफोर्स का सपोर्ट मिला है।

2020 से 2024 के बीच, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), ब्लॉकचेन, आईओटी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), एज कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, इस तेजी से हुई प्रगति ने एक महत्वपूर्ण स्किल गैप पैदा कर दिया है, जिसमें केवल 2.5 प्रतिशत भारतीय इंजीनियर एआई में दक्ष हैं और केवल 5.5 प्रतिशत के पास बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, इस बढ़ते टेक्नोलॉजी स्किल्स गैप को कम करने के लिए, 86 प्रतिशत भारतीय कंपनियां अपने आईटी वर्कर्स को सक्रिय रूप से रिस्किल कर रही हैं। आने वाले सालों में आईटी सेवाओं का उद्योग भी विस्तार के लिए तैयार है, जिसमें अगले पांच सालों में क्लाउड निवेश में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खुली छूट

ढाका (ईएमएस)। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलने लगी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक आतंकी को जेल से रिहा किया है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जो अल-कायदा से प्रेरित आतंकी संगठन है, इस अब अंसार अल इस्लाम के नाम से जाना जाता है उसके प्रमुख मुफ्ती जाशिमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया।गाजीपुर के काशिमपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से आंतकी को रिहा कर दिया गया। आतंकी संगठन बांग्लादेश में ब्लॉगर्स और अन्य लोगों की हत्या करता रहा है।

यूक्रेन का दावा, कुर्स्क क्षेत्र में100 बस्तियों पर कब्जा किया

कीव (ईएमएस)। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसने के बाद से यूक्रेनी सैनिकों ने 100 बस्तियों पर कब्जा किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में सिरस्की के हवाले से कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं, रूसी सैनिकों को महत्वपूर्ण नुकसान हो रहा है।

रिपोर्ट में बताया कि रूस ने अन्य क्षेत्रों से करीब 30,000 सैनिकों को कुर्स्क में फिर से तैनात किया है और यूक्रेनी बलों को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके विशेष बलों ने कुर्स्क क्षेत्र के सुदझा जिले में एक ऊंचाई वाली जगह को सुरक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया है। यह क्षेत्र पहले यूक्रेन के कब्जे में था।

यह ऊंचाई वाली जगह यूक्रेनी ठिकानों से 400-500 मीटर दूर स्थित है। रूसी सैनिक अब यूक्रेनी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। सिरस्की ने कहा कि यूक्रेन ने अपने सुमी क्षेत्र में गोलीबारी को रोकने के लिए एक बफर जोन बनाने के उद्देश्य से कुर्स्क में अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनके सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने 594 रूसी सैनिकों को पकड़ लिया है। सिरस्की के अनुसार, रूस अन्य मोर्चों से सैनिकों को वापस बुलाकर यूक्रेन का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में पोक्रोवस्क मोर्चे से सेना वापस नहीं हटा रहा है, जहां उन्होंने कहा कि स्थिति कठिन बनी हुई है।

5-6 अगस्त की रात से ही कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना ने सुदजा शहर के पास क्षेत्र में प्रवेश किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर बड़े पैमाने पर उकसाने और अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप लगाया, तथा इस आक्रमण को आतंकवादी हमला बताया।

चीनी इकाइयों पर अमेरिकी प्रतिबंध अवैध और एकतरफा

बीजिंग,(ईईएमएस)। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान के बीजिंग जाने से पहले चीन ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी इकाइयों पर अमेरिकी प्रतिबंधों को अवैध और एकतरफा और तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। पिछले सप्ताह अमेरिका ने यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए चार सौ से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों पर बैन लगा दिया था, जिनमें चीनी कंपनियां भी शामिल थीं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे रुस को प्रतिबंधों से बचने और अपनी सेना का निर्माण करने में मदद करते हैं। अमेरिका ने रूस के रक्षा औद्योगिक आधार के समर्थन पर चीन को कई बार चेतावनी दी है और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकियों का दोहन करने की रुस की क्षमता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगा चुका है।

यूरेशियन मामलों के लिए चीन के विशेष दूत, ली हुई जिन्होंने शटल कूटनीति के चार दौर किए उन्होंने ब्राजील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों के साथ बैठकों के बाद चीन में राजदूतों के लिए एक ब्रीफिंग में प्रतिबंधों का विरोध किया था। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सुलिवन की चीन के विदेश मंत्रालय में उत्तरी अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र मामलों के प्रमुख यांग ताओ ने अगवानी की। इस मौके पर चीन में अमेरिका के राजदूत निकोलस बर्न भी मौजूद थे।

अरे बाबा रे.....100 बच्चों के पिता हैं टेलीग्राम के सीईओ

पेरिस (ईएमएस)। साढ़े 15 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 120वें सबसे अमीर शख्स जो न सिर्फ एक बिजनेस टॉयकून है। बल्कि लग्जरी लाइफ स्टाइल और मौजमस्ती करना उसका शौक है। हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव की हैं। रूसी मूल के अरबपति पावेल डुरोव जो कि टेलीग्राम के सीईओ हैं। उन्हें पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बीच डुरोव को लेकर एक खुलासा हुआ है कि 39 साल के पावेल 100 बच्चों के पिता हैं। वे भी बिना शादी के, लेकिन कैसे।

टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ डुरोव हैं। जो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। डुरोव की गिरफ्तारी के बाद उनसे जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। डुरोव 100 से ज्यादा बच्चों के पिता हैं। मगर 39 साल के पावेल डुरोव ने अब तक शादी नहीं की है। दावा है कि पावेल डुरोव की दर्जनों गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। गौरतलब है कि सीईओ के 100 बच्चों के पिता होने का दावा खुद पावेल डुरोव ने किया है।

डुरोव ने दावा किया था कि स्पर्म डोनर के तौर पर वह 100 से ज्यादा बच्चों के जैविक पिता बन चुके हैं। दोस्त के अनुरोध पर 15 साल पहले उन्होंने स्पर्म डोनेशन शुरू किया था। जांच में पता चला था कि डुरोव का स्पर्म अच्छी क्वॉलिटी वाला है। यही वजह है कि उनके स्पर्म के लिए महिलाएं घंटों लाइन में लगती है।

डुरोव जिन्हें पिछले दिनों फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। फ्रांस की कोर्ट ने मंगलवार को उनको हिरासत 2 दिनों के लिए और बढ़ा दी। डयूरोव पर आरोप है कि उन्होंने टेलिग्राम के जरिए चाइल्ड पोर्न सहित क्रिमिनल केंटेट फैलाया है।

सारी दुनिया से जल्दी ही बंद होगा टेलीग्राम - सरकारों को पसंद नहीं है, आम नागरिकों की निजता

पेरिस (ईएमएस)। मैसेजिंग एप टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पावेल के खिलाफ 12 मामले फ्रांस में दर्ज हैं। इसके बाद भी वह अपनी महिला मित्र के साथ पेरिस पहुंचा था। जहां उनकी गिरफ्तारी हो गई है।

दुनिया भर की सभी सरकारें टेलीग्राम से संदेश भेजे जा रहे हैं। उसे सरकार के साथ शेयर करने की मांग कर रहे हैं। रूस ने भी यह मांग की थी। जिसे पावेल डुरोप ने नहीं माना था। जिसके कारण उन्हें अपनी जन्मभूमि रूस को छोड़कर रातों-रात भागना पड़ा था। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, भारत,रूस इत्यादि देश यह चाहते हैं। टेलीग्राम के जो भी संदेश भेजें जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से उनका एक्सेस सरकार को दिया जाना चाहिए। टेलीग्राम यह एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है, निजता अधिकार के तहत मैसेजिंग सिस्टम में किसी भी सरकार को छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उल्लेखनीय है, इस मैसेजिंग कंपनी में केवल 30 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप ढाई लाख करोड रुपए का है। अमेरिका ने टेलीग्राम के एक इंजीनियर के माध्यम से टेलीग्राम मैसेजिंग सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की थी। अमेरिका इसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बाद से ही टेलीग्राम के सीईओ पावेल के ऊपर कई देशों में अपराधिक प्रकरण दर्ज कर मैसेजिंग सिस्टम को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।

मानव अधिकार कानून के तहत जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून बने हुए हैं। उसके अनुसार टेलीग्राम पर सीधे-सीधे कोई कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। अब अपराधिक प्रकरण दर्ज कर टेलीग्राम को बंद करने का सुनयोजित प्रयास दुनिया के बड़े देश कर रहे हैं।

टेलीग्राम के सीईओ पावेल के खिलाफ बाल यौन शोषण,सामग्री के आदान-प्रदान मे ड्रग ट्रैफिकिंग और संगठित अपराध को बढ़ावा देने के आरोप मे अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे है। फ्रांस की अदालत ने उन्हें पुलिस कस्टडी में सौंप दिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

भारत में भी की जा रही है जांच

भारतीय गृह मंत्रालय और आईटी विभाग टेलीग्राम के मैसेजिंग सिस्टम को लेकर जांच कर रहा है। भारत सरकार ने भी टेलीग्राफ से मैसेज पर नियंत्रण करने की सुविधा मांगी गई थी। टेलीग्राफ के सीईओ ने सरकार को मैसेज डिकोड करने का अधिकार नहीं दिया। जिसके कारण भारत सरकार जल्द ही टेलीग्राम पर कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सकती है।

तानशाह ने किया नई तकनीक से युक्त मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण

सियोल (ईएमएस)। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग-उन ने एक नई तकनीक से युक्त 240 मिमी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के परीक्षण में हिस्सा लिया। अटकलें हैं कि यह नया आर्टिलरी सिस्टम रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उपयोग करने के लिए मिल सकता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, किम ने मल्टीपल रॉकेट लांच सिस्टम (एमआरएलएस) के परीक्षण में भाग लिया। बताया जा रहा हैं कि हथियार सियोल और उसके आस-पास के इलाकों में टारगेट रेंज में रख सकता है।

फरवरी में, उ.कोरिया ने कहा था कि एक नया रॉकेट लांचर विकसित किया है। जो सटीकता और रेंज के मामले में उसकी हथियार क्षमताओं को बढ़ा सकता है। मई में उत्तर कोरिया की तरफ से कहा गया कि वह 2024 और 2026 के बीच कोरियन पीपुल्स आर्मी यूनिट में हथियार प्रणाली तैनात करेगा। पर्यवेक्षकों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उ.कोरिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उपयोग के लिए रूस को रॉकेट लांचर की आपूर्ति करने के प्रयास में रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण कर रहा है।

कोरिया इंस्टीटयूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के एक वरिष्ठ शोधकर्ता ने बताया कि परीक्षण का उद्देश्य 1980 के दशक में निर्मित उत्तर कोरिया के पुराने 240 मिमी एमआरएलएस में सुधार करना है। उन्होंने संभावना जाहिर कि यह परीक्षण दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास की प्रतिक्रिया का एकरूप होसकता है। यह परीक्षण तब हुआ जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका अपना वार्षिक ग्रीष्मकालीन उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित कर रहे हैं, जो गुरुवार को समाप्त होने वाला है।

कर्मचारी करोड़पति हो गए, पैसा खर्च करने और परिवार के लिए समय नहीं

सांता क्लारा (ईएमएस)। अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से आशा से अधिक कमाई कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारी करोड़पति हो चुके हैं। जो कमाई कर्मचारियों ने की है। उसे खर्च करने के लिए उनके पास समय नहीं है।

इस कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर काम का इज्जत इतना बोझ है। वह सप्ताह के सातों दिन बिना छुट्टी के काम करते हैं। पैसे कमाने के लिए ओवरटाइम करते हैं। कंपनी से उन्हें आसानी से छुट्टी नहीं मिलती है। कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, वह ओवरटाइम करें।

फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी महंगी महंगी कारों से फैक्ट्री में आते हैं। 12 से 14 घंटे काम करते हैं। इसके बाद भी मांग के अनुसार कंपनी चिप की आपूर्ति नहीं कर पा रही है।

2019 में इस कंपनी की शुरुआत एनवीडीया द्वारा की गई थी। कंपनी को एआई के लिए जरूरी चिप बेचने से बड़ा लाभ हुआ है। चिप की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग है। मांग के अनुपात में उत्पादन कम है। कंपनी अपने कर्मचारियों को उत्पादन के हिसाब से अच्छा वेतन और बोनस देती है।

इस कंपनी के मालिक जेनसेन का कहना है। कुछ नया करने और कमाने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। कर्मचारियों से ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की अपेक्षा करते हैं, कंपनी में काम करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। पैसा कमाने के चक्कर में कर्मचारी बिना साप्ताहिक अवकाश के ओवरटाइम करते हैं। पैसा तो कर्मचारियों ने बहुत कमा लिया है। लेकिन अब इसको खर्च करने का उन्हें समय नहीं मिल रहा है। नाही शरीर को आराम मिल पा रहा है। जिसका असर परिवार में लड़ाई और आपसी विवाद के रूप में सामने आ रहा है। कर्मचारियों में निरंतर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ने लगा है।

अगस्त माह में 11 कंपनियों ने वापस खरीदे अपने शेयर

मुंबई (ईएमएस)। अगस्त 2024 में शेयर बाजार पर शेयरों के बायबैक की बौछार हो रही है। अगस्त माह में 11 कंपनियों ने अब तक 5,388 करोड़ रुपये के शेयरों को वापस खरीदा है। एक डेटा के मुताबिक, रुपये के लिहाज से खरीदे गए शेयरों की मात्रा 14 माह में सबसे ज्यादा है। बता दें कि बायबैक के तहत कंपनियां अपने शेयरों को निवेशकों से एक तय कीमत पर वापस खरीदती हैं। साधारण तौर पर ये कीमतें मौजूदा शेयरों की कीमतों से ज्यादा होती है।

जून 2023 में विप्रो सहित दो कंपनियों ने मिलकर 12,005 करोड़ के शेयरों का बायबैक किया था। इसमें विप्रो का बायबैक 12,000 करोड़ रुपये का था। अगर विप्रो, सितंबर 2023 में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के 10,000 करोड़ रुपये, दिसंबर 2023 और मार्च 2022 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के 17,000 करोड़ और 18,000 करोड़ रुपये के बायबैक को छोड़ दिया जाए, तब मौजूदा महीने का बायबैक दिसंबर 2022 के बाद से सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2022 में 9 कंपनियों ने 10,606 करोड़ के शेयरों का बायबैक किया था।

जानकारों का कहना है कि शेयर बायबैक की मात्रा में तेजी का कारण अक्टूबर 2024 से भारत के शेयर बायबैक टैक्स रिजीम में महत्वपूर्ण बदलाव हैं। जुलाई 2024 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में नए नियमों से बायबैक स्ट्रैटेजी का नजरिया फंडामेंटली बदल जाएगा, क्योंकि टैक्स का बर्डेन कंपनियों से हटकर शेयरहोल्डर्स पर आएगा।

मौजूदा समय में, बायबैक करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत से अधिक बायबैक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वहीं, शेयरहोल्डर्स को उनके शेयरों की ऑफरिंग पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले नए रिजीम के तहत, शेयरों के बायबैक पर मिले पूरे अमाउंट को निवेशकों के टैक्स स्लैब के हिसाब से लाभांश (डिविडेंड) के रूप में टैक्स लगाया जाएगा। बायबैक में ऑफर किए गए शेयरों की खरीदारी की लागत को कैपिटल लॉस के रूप में माना जाएगा और उसे अन्य कैपिटल गेन के लिए एडजस्ट या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा।

हिंडनबर्ग ने अब सुपर माइक्रो कंप्यूटर इंक को लेकर किया खुलासा

-अकाउंटिंग में हेराफेरी का लगाया आरोप, औंधे मुंह गिरे शेयर

नई दिल्ली,(ईएमएस)। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में एक आईटी फर्म पर निशाना साधा गया है। यह कंपनी सिलिकॉन वैली स्थित सुपर माइक्रो कंप्यूटर इंक है। हिंडनबर्ग ने इस कंपनी पर अकाउंट में हेराफेरी का आरोप लगाया है। नैस्डैक पर सूचीबद्ध इस कंपनी के शेयरों में 27 अगस्त को प्री-मार्केट ट्रेड में करीब आठ फीसदी की गिरावट आई। हिंडनबर्ग का दावा है कि उनकी रिपोर्ट तीन महीने की जांच पर आधारित है। रिपोर्ट में अकाउंट में हेरफेर, अन-डिजक्लोज्ड लेनदेन के सबूत, प्रतिबंध और एक्सपोर्ट कंट्रोल में विफलता और ग्राहकों की समस्याओं की बात कही गई है।

हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में कहा कि सुपर माइक्रो कंप्यूटर इंक को 2018 में वित्तीय विवरण दाखिल करने में विफल रहने के चलते नैस्डैक से अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। बाद में एसईसी ने बड़े स्तर पर अकाउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप कंपनी पर लगाया था। इस गड़बड़ी का संबंध 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा का अनुचित रूप से मान्यता प्राप्त रेवेन्यू और कम करके बताए गए खर्चों से था। इसकी वजह से कंपनी की बिक्री, आय और मुनाफे में बढ़ोरती हुई थी।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मुकदमेबाजी के रिकॉर्ड और पूर्व कर्मचारियों के साथ साक्षात्कार का हवाला देते हुए सुझाव दिया गया है कि कंपनी ने 17.5 मिलियन के एसईसी समझौते के तीन महीने बाद ही अकाउंटिंग घोटाले में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों को फिर से काम पर रखा है। हिंडनबर्ग ने सुपर माइक्रो कंप्यूटर इंक के पूर्व सीएफओ हावर्ड हिदेशिमा को इस घपलेबाजी में शामिल बताया है और कहा है कि इन्हें सुपर माइक्रो से संबंधित एक कंपनी में फिर से काम पर रख लिया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अकाउंटिंग और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण प्रमुख कंपनियों ने सुपर माइक्रो कंप्यूटर इंक के साथ या तो व्यापार कम कर दिया है या पूरी तरह खत्म कर दिया है। हिंडनबर्ग ने सुपर माइक्रो कंप्यूटर के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ली है। इसमें कहा गया है, यह रिपोर्ट हमारी राय है और हम प्रत्ये

गुजरात के इन 12 जिलों में कल रेड अलर्ट, मौसम विभाग का अगले छह दिनों तक भारी से भारी बारिश का अनुमान

अहमदाबाद,28 अगस्त

गुजरात में भारी बारिश: राज्य के सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के अधिकांश हिस्सों में मेघराजा की मारपड़ीहै,कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।इसकेअलावाकई निचले इलाकों में बाढ़ आने के कारण कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जहां राज्य में पिछले तीन दिनों से भारी से बहुतभारी बारिश हो रही है,वहींमौसम विभाग ने राज्य में अगले छह दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। जिसमें इसमहीनेकेअंततकसौराष्ट्र के अधिकांश और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी. वहीं कल (29 अगस्त) सौराष्ट्र के 12 जिलों कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट,जामनगर,बोटाद, भावनगर, अमरेली,जूनागढ़,गिरसोमनाथ, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट घोषित किया गया है.पिछले24 घंटों में राज्य के250तालुकाओं में बारिश हुई है. आइए जानते हैंअगले छह दिनों तक कैसा रहेगा बारिश का मौसम।

पिछले 24 घंटों में राज्य के 250 तालुकाओं में बारिश हुई है. जिसमें देवभूमि द्वारका के खंभालिया में 454 मिमी, जामनगर में 387 मिमी, जामजोधपुर में 329 मिमी, लालपुर में 324मिमी. और कालावाड में 284 मिमी, पोरबंदर के राणावाव में 292 मिमी, राजकोट के लोधिका और देवभूमि द्वारका के भनवाद में 268मिमी,राजकोट के कोटदासघानी में261मिमी,देवभूमि द्वारका के कल्याणपुर में 260मिमी। और द्वारका में 251 मिमी, पोरबंदर में 252 मिमी। बरस गया बादल का पानी।

वहीं मौसम विभाग ने आज (28 अगस्त) कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, जामनगर, राजकोट, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारीकियाहै।जबकिपाटन, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा मध्य और उत्तरगुजरातकेबनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा,अरावली,खेड़ा, गांधीनगर, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदेपुर जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल (29 अगस्त) सौराष्ट्र के12जिलों कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट,जामनगर,बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट घोषित कियागया है। , देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिले। इसके अलावा उत्तरगुजरात,मध्य गुजरातऔर दक्षिण गुजरातसमेत21जिलों में कोई चेतावनी घोषित नहीं की गई है.राज्य में इस महीने केअंत तक सौराष्ट्र के अधिकांश और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 30 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिशकेबादकच्छ,मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट जामनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

गुजरात में अभी भी भारी बारिश की आशंका, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम भूपेन्द्र पटेल से की बात

अपडेट किया गया: 28 अगस्त,

गुजरात में भारी बारिश को लेकर सीएम भूपेन्द्र पटेल से पीएम मोदी की टेलीफोनिक बातचीत: पिछले कुछ दिनों से राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, वहीं मौसम विभाग ने अगले छह दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारी बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से फोन पर बातचीत की और राज्य में भारी से भारी बारिश के बीच राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली.

वहीं मौसम विभाग ने आज (28 अगस्त) कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, जामनगर, राजकोट, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि पाटन, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा मध्य और उत्तर गुजरात के बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, गांधीनगर, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदेपुर जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अपने सोशल मीडिया माध्यम 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारी बारिश की स्थिति को लेकर मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की और राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने नागरिकों के जीवन और पशुधन की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही, गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। प्रधानमंत्री गुजरात को लेकर चिंतित हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.उनके दिल में गुजरात के लोगों के प्रति गहरा स्नेह है।' प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और जब भीजरूरत पड़ी वह हमेशा राज्य के लोगों के साथ खड़ी रही हैं।'

राज्य में पिछले तीन दिनों से भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिससे राज्य के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। साथ ही कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात भी बन गए हैं. वहीं, मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है. इस बीच, भूपेन्द्र पटेल ने राज्य के प्रमुख शहरों के जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल (29 अगस्त) सौराष्ट्र के 12 जिलों कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट घोषित किया गया है। , देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिले।

गुजरात में बाढ़ की स्थिति से निपटने सेना हरकत में, जारी किया हेल्पलाइन नंबर

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में भारी बारिश के बाद अधिकांश जिलों में बाढ़ से हालात हैं बिगड़े हालात से निपटने के लिए अब भारतीय सेना हरकत में आ गई है और राज्य के विभिन्न जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरफ के साथ राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं केंद्र सरकार की सतर्कता और राज्य के स्टैंड-बाय दृष्टिकोण के कारण आपदा के दौरान पीड़ितों तक मदद पहुंच रही है। सेना ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की भी घोषणा की है। बाढ़ पीड़ित मदद के लिए आर्मी टीम के हेल्पलाइन नंबर 079-23201507 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के भीतर सेना की छह टुकड़ियां तैनात की गई हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर स्थिति पर नजर रखने के लिए गांधीनगर मिलिट्री स्टेशन से सेना की टीमें तैनात की जा रही हैं। वडोदरा में हालात बेहद खराब होने के कारण सेना की तीन टुकड़ियां वहां भेजी गई हैं जबकि सेना की एक टुकडी मोरबी में और दो टुकडियां आणंद और खेड़ा में तैनात की गई हैं सेना की ये टीमें आधुनिक बचाव उपकरण, जरूरी दवाइयां, मेडिकल टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं मानवीय और सहायक दृष्टिकोण के साथ, सेना और राज्य सरकार के संबद्ध विभाग और स्थानीय प्रशासन एक-दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाढ़ पीड़ितों तक समय पर सहायता पहुंचे और बचाव और राहत अभियान जल्द से जल्द चलाया जाए। स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर स्थिति पर नजर रखने के लिए गांधीनगर मिलिट्री स्टेशन से सेना की टीमें तैनात की जा रही हैं। गुजरात में अब तक 17,827 लोगों को निकाला जा चुका हैं 1,653 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ की 13 टीमें और एसडीआरएफ की 22 टीमें प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं।

राज्य में भारी बारिश के चलते जीएसआरटीसी की बस सेवा प्रभावित, 4531 ट्रीपें रद्द

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरातभर में हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ हैं भारी बारिश का असर रेल और बस सेवा पर बुरा असर हुआ हैं राज्य में पिछले दो दिनों से शैक्षिक कार्य बंद हैं राज्य में बारिश के कारण गुजरात राज्य पथ परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) की बस सेवा बंद कर दी गई हैं राज्य में 1,000 से ज्यादा रूटों पर बस ठप हो गई हैं जीएसआरटीसी ने 4,000 से ज्यादा ट्रीपें रद्द कर दी हैं जानकारी के मुताबिक कल की तरह आज भी एसटी की बस सेवा प्रभावित हुई हैं आज भी राज्य भर में 1180 रूट बंद हैं और अब तक 4,531 ट्रीपें रद्द किए जाने की जानकारी हैं भारी बारिश के कारण आज गुजरात के वडोदरा, पादरा, खेड़ा डिपो के सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं। मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात की ओर जाने वाले मार्ग अधिक प्रभावित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बस सेवाएं और ट्रीपें रद्द होने से एसटी निगम को अनुमानित 1.08 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

10 फीट तक बाढ़ की बात स्वीकार करते हुए मंत्रियों को डंपरों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना पड़ा।

वडोदरा ,28 अगस्त

बाढ़ प्रभावित वडोदरा का दौरा करने आए राज्य सरकार के दो मंत्रियों की निगम के डंपर में बैठने की बारी थी। वडोदरा के कुछ इलाकों में इस हद तक पानी भर गया है कि निगम तंत्र ने मंत्रियों को कम ऊंचाई वाले ट्रकों या बसों में बिठाने का जोखिम नहीं उठाया और ऊंचे डंपर का ऑर्डर दिया। इस डंपर में सीढ़ी लगाकर मंत्री ऋषिकेष पटेल और जगदीश विश्वकर्मा को ऊपर चढ़ाया गया. इसके बाद उन्होंने अकोटा समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया.

मंत्रियों ने वडोदरा कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, विधायकों सहित नेताओं और विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि देव बांध और अजवा झील के अपस्ट्रीम में भारी बारिश के कारण लगातार पानी का प्रवाह हो रहा है और इन दोनों जलाशयों से पानी छोड़ा गया है. शहर के कई इलाकों में दस-दस फीट तक पानी भर गया है. राज्य सरकार ने बचाव और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है.

उन्होंनेआगेकहाकि एनडीआरएफ औरएसडीआरएफकीअधिक टुकड़ियों के साथ-साथ सेना की टुकड़ियों की भी मदद की जा रही है. ताकि बचाव कार्य तेजी से किया जा सके. अब तक 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. 1200 लोगों को बचाया गया है. इन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है. एक लाख से अधिक भोजन के पैकेट तैयार किये गये हैं और सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ है।

उकाई बांध के ऊपरी हिस्से में बारिश थमने से सूरत प्रशासन ने ली राहत की सांस, बाढ़ का खतरा टला

सूरत (ईएमएस) पिछले तीन दिनों से तापी नदी में संभावित बाढ़ को लेकर सूरत शहर पर छाए चिंता के बादल अब छंट गए हैं। कल रात से उकाई बांध के ऊपरी हिस्से में बारिश बंद होने से सूरत प्रशासन ने राहत की सांस ली हैं उकाई बांध में इनफ्लो कम हुआ है, बांध का आउटफ्लो भी काफी कम हो गया है। आज सुबह से उकाई बांध से तापी नदी में 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा हैं जिसका सीधा असर तापी नदी के जलस्तर पर देखने को मिल रहा हैं तापी नदी के जलस्तर में कुल मिलाकर कमी आने से कादरशा की नाल, वेडरोड पंडोल सहित निचले इलाकों में सीवेज का पानी उतरने से नागरिकों को राहत मिली है। दक्षिण गुजरात समेत पूरे राज्य में आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा हैं वडोदरा, अहमदाबाद समेत कई शहरों में जलजमाव की स्थिति के बीच सूरत शहर में पिछले तीन दिनों से तापी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे संभावित बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई हैं जैसे ही उकाई बांध से2.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नगर निगम प्रशासन ने सभी फ्लड गेट बंद करने का फैसला किया। जिसके चलते सेंट्रल और कतारगामजोन के निचले इलाकों में सीवेजकाबैक-अप होने से प्रशासन स्थिति पूर्ववत करने के प्रयासो में जुट गया हैं खासकर कादरशा की नाल, धास्तीपुरा और वेडरोड पंडोल समेत इलाके में गटर के पानी के कारण वाहन चालकों समेत स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ हांलाकि उकाई बांध के ऊपरी हिस्सों में बारिश थमने से पानी की आय में कमी आई है। वर्तमान में उकाई बांध में एक लाख क्यूसेक के इनफ्लो के मुकाबले तापी नदी में 1.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिसके चलते कल तक दोनों किनारों पर विकराल रूप में बहने वाली तापी नदी की सतह भी काफी कम हो गई है। वर्तमान में कॉजवे का लेवल भी 10 मीटर से घटकर 9.50 मीटर रह गया है। परिणामस्वरूप, नावडी सहित निचले इलाकों में भी नदी का पानीकमहोगया। कि मौसम विभाग द्वारा अगले दो दिनों तक सूरत सहित दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच आज सुबह जिले के उमरपाड़ा में सबसे अधिक दो इंच बारिश हुईईसकेअलावा बारडोली और कामरेज में करीब एक इंच बारिश हुई हैं इसके अलावा पलसाणा में डेढ़ इंच और ओलपाड में आधा इंचबारिश दर्ज की गई हैं वहीं सूरत शहर मेंसेंट्रल जोन और वराछा जोन बी में आधा इंच बारिश को छोड़कर अन्य जोन इलाकों में हल्की बारिश की बौछारें दर्ज की गई हैं

पुलिस ने मरीजों को बचाया, वडसर में गंभीर मरीज की मदद के लिए पहुंचे वलाखान

वडोदरा ,28 अगस्त

वडोदरा में बाढ़ के दौरान बीमारों, विकलांगों औरबुजुर्गों की हालत बेहद दयनीयहोगई है. पुलिस फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की मदद में भी जुटी है.फतेगंज क्षेत्र के विश्वामित्री के पास स्थित नरहरि हॉस्पिटल में बाढ़ का पानी दोबारा बढ़ने से भर्ती मरीजों की हालत दयनीय हो गई है. इनमें से जो मरीज शिफ्ट होना चाहता था, पुलिस उसकी मदद के लिए आई। और एक माह को पुलिस खाट पर उठाकर दूसरी जगह ले गई.

दूसरी ओर, विश्वामित्री के पास वडसर गांव में चमगादड़ बन गया है और सोलंकी वास में एक मरीज गंभीर हो गया और फायर ब्रिगेड की मदद मांगी गई। लेकिन सुबह से शाम पांच बजे तक उन्हें मदद नहीं मिली. इसलिए लोगों में आक्रोश की भावना थी.

वडोदरा मंडल में भारी बारिश और जलभराव के कारण पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित

वडोदरा मंडल में लगातार बारिश और जलभराव के कारण पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई ट्रेनें निरस्त, आंशिक रूप से निरस्त और डायवर्ट की गई हैं।

पश्चिमरेलवेकेमुख्यजनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी विज्ञप्ति केअनुसार, मुंबई से रवाना होने वाली प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

29 अगस्त, 2024 को यात्रा प्रारंभ करने वाली निरस्त ट्रेनें:

1. ट्रेन संख्या 14708 दादर - लालगढ़ रणकपुर एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 09724 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर स्पेशल
3. ट्रेन संख्या 12979 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस - जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस
5. ट्रेन संख्या 04712 बांद्रा टर्मिनस - बीकानेर स्पेशल
6. ट्रेन संख्या 19003 दादर - भुसावल खानदेश एक्सप्रेस
7. ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस
8. 30 अगस्त, 2024 को यात्रा प्रारंभ करने ट्रेन संख्या 19015 दादर - पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन / शॉर्ट ओरिजिनेशन / आंशिक रूप से निरस्त ट्रेन:

1. 29 अगस्त, 2024 की ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस - श्री गंगानगर अरावली एक्सप्रेस अजमेर से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इसलिए बांद्रा टर्मिनस और अजमेर के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इसे ध्यान में रखकर यात्रा करें।

भारतीय रेल का गणपति महोत्सव पर सौगात बांद्रा टर्मिनस और मडगांव केबीच एक नई द्वि-साप्ताहिक ट्रेन शुरू की जाएगी

मुंबई के पश्चिमी उपनगरों से कोकण क्षेत्र को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल; माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस शुभारम्भ समारोह में नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

इस साल आगामी गणपति महोत्सव के शुभ अवसर का जश्न मुंबईकरों के लिए समय से पहले ही शुरू हो गया है। कोकण क्षेत्र को बेहतर ट्रेन कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयास में पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और मडगांव स्टेशनों के बीच एक नई द्वि-साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार, 29 अगस्त, 2024 को दोपहर 13.25 बजे बोरीवली रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

नई ट्रेन 10115/10116 बांद्रा टर्मिनस - मडगांव एक्सप्रेस मुंबई के व्यस्त पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के सुंदर तटीय क्षेत्र और मडगांव शहर के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से, मुंबई के पश्चिमी उपनगरों के निवासियों का कोंकण क्षेत्र से सीधा संपर्क होगा। यह कदम त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। यह ट्रेन एक सीधा, सस्ता और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करेगी। नई ट्रेन सेवा पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय होगी क्योंकि यह ट्रेन सुरम्य सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरेगी, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। यह द्वि-साप्ताहिक ट्रेन इस मार्ग पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी मदद करेगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों, पर्यटन और आस-पास के क्षेत्रों में व्यापार को लाभ होगा।

उद्घाटक सेवा के रूप में इस ट्रेन को बोरीवली स्टेशन से ट्रेन संख्या 09167 बोरीवली-मडगांव स्पेशल के रूप में रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन 29 अगस्त, 2024 को बोरीवली से 13.25 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 04.00 बजे मडगांव पहुंचेगी। यह वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, वीर, चिपलून, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, सावंतवाड़ी रोड, थिविम और करमाली स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी) क्लास, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास डिब्बे होंगे। उद्घाटक सेवा की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है।

वडोदरा, देवभूमि द्वारका और जामनगर में राहत और बचाव कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश

- एनडीआरएफ की पांच अतिरिक्त टीमों और सेना की चार कॉलम को वडोदरा मोबिलाइज करने के निर्देश
- बाढ़ में फंसे लोगों को फूड पैकेट, पानी के पाउच और आवश्यक दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था को प्राथमिकता
- मुख्यमंत्री ने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के राहत एवं बचाव कार्यों तथा बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की

गांधीनगर (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को गांधीनगर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के राहत एवं बचाव कार्यों तथा बाढ़ की स्थिति की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से वडोदरा शहर एवं जिले, देवभूमि द्वारका तथा जामनगर जिले में पानी में फंसे लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उधर, वडोदरा में राहत और बचाव कार्यों का मार्गदर्शन कर रहे स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री को बाढ़ और लोगों के घरों में पानी भरने के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को पानी उतरने तक फूड पैकेट, पीने के पानी का पाउच और स्वास्थ्य रक्षक दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इतना ही नहीं, प्रभावित जिलों में जहां कहीं भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, उसे भी शीघ्रता से बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पानी कम होने पर तुरंत ही कीचड़, मिट्टी और पानी के साथ बहकर आई झाड़ी-टहनी और पत्तियों आदि के मलबे को हटाने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू करेगी। कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के माध्यम से संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के उपाय भी तत्काल शुरू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार सुबह से ही इन सभी कार्यों को क्रमशः शुरू करने और जनजीवन को तेजी से बहाल करने के उपायों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए। उन्होंने वडोदरा शहर एवं जिले के लिए सूरत, आणंद, खेड़ा, भरूच, छोटा उदेपुर और अहमदाबाद से बड़ी संख्या में फूड पैकेट और पीने के पानी के पाउच पहुंचाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिए। वहीं, राजकोट और सौराष्ट्र के अन्य जिलों, जहां वर्षा की तीव्रता घट गई है या रुक गई है, वहां से इन वस्तुओं को जामनगर और देवभूमि द्वारका में मोबिलाइज किया जाएगा।

बैठक में इस बात के भी निर्देश दिए गए कि वडोदरा में बाढ़ का पानी उतरने की शुरुआत होते ही शहरी विकास विभाग और नगर पालिका निदेशक के साथ समन्वय कर अहमदाबाद महानगर पालिका, सूरत महानगर पालिका तथा भरूच एवं आणंद नगर पालिका की टीमें सफाई उपकरणों और कीटनाशक दवाइयों के साथ आवश्यक साफ-सफाई के काम में जुट जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने वर्षा से अत्यधिक प्रभावित जिलों में जलजनित या वाहक जनित रोगों को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा टीमों को आवश्यक दवाइयों के साथ सूरत, भावनगर, गांधीनगर और राजकोट से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा से प्रभावित सभी जिलों में कैशडोल्स और घरेलू समान की सहायता के भुगतान का काम भी तत्काल शुरू करने के लिए मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा शहर में अभी भी बाढ़ के पानी की यथावत स्थिति और जनजीवन के प्रभावित होने के हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए आणंद, नर्मदा, सुरेन्द्रनगर और वलसाड से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की पांच अतिरिक्त टीमों तथा आणंद, खेड़ा और गांधीनगर से सेना की 4 कॉलम को मोबिलाइज करने को कहा। इसके अलावा, अहमदाबाद और सूरत से रेस्क्यू बोट भी वडोदरा पहुंचेगी। जामनगर और देवभूमि द्वारका में वर्षा की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जो लोग अभी भी पानी में फंसे हुए हैं, उनके स्थानांतरण के लिए वायुसेना और कोस्ट गार्ड की मदद लें और रेस्क्यू व्यवस्था का समन्वय करें। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए फूड पैकेट तथा आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए सेवाभावी संगठनों और स्वैच्छिक संस्थाओं से फूड पैकेड और आवश्यक खाद्य सामग्री तैयार करने तथा उनके वितरण के लिए समुचित प्रबंध करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव राज कुमार ने राज्य में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में आगामी 48 घंटों तक बारिश के भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के संदर्भ में इन क्षेत्रों के कलेक्टरों को भी सतर्क एवं सजग रहने को कहा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव पंकज जोशी और एम.के. दास तथा राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क एवं भवन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव उपस्थित रहे।

केन्द्र ने 6456 करोड़ की तीन परियोजनाओं को दी मंजूरी,1.14करोड़ रोजगार का सृजन होगा

अहमदाबाद (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने रेल मंत्रालय की लगभग 6,456 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से दूर-दराज़ के इलाकों को आपस में जोड़कर लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, मौजूदा लाइन क्षमता बढ़ाने और परिवहन नेटवर्क का विस्तार करने के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा जिससे तेजी से आर्थिक विकास होगा।

नई लाइन के प्रस्तावों से सीधी कनेक्टिविटी बनेगी और आवागमन में सुधार होगा, तथा भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा संबंधी विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर बेहद जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नए भारत की परिकल्पना के अनुरूप हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास होगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा और उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना तैयार किए जाने से संभव हुआ है और यह लोगों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे 4 राज्यों के 7 जिलों में लागू की जाने वाली तीन परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

इन परियोजनाओं के साथ 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे दो आकांक्षी जिलों (नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम) को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नई लाइन परियोजनाओं से लगभग 1,300 गांवों और लगभग 11 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1,300 गांवों और लगभग 19 लाख लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। ये मार्ग कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 45 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।

बड़ौदा डेयरी के दूध की कालाबाजारी, डेयरी ने पुलों पर टैंपा लगाकर दूध बांटा

वडोदरा ,28 अगस्त

बाढ़ की विकट स्थिति से जूझ रहे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने दूध की कालाबाजारी की और खुली लूट को अंजाम दिया.

वडोदरा में जब लोग विश्वामित्री नदी की बाढ़ से पैदा हुई भयावह स्थिति में फंसे हुए थे तो कुछ लोग उनकी मजबूरी काफायदा उठाने से नहीं चूके. कईजगहों पर डेयरी पाउच को ब्लैक कर दिया गया और लोगों ने 50 रुपये में पाउच खरीदा. इसी तरह सब्जियों की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया और कीमतें दो से तीन गुना तक बढ़ गईं।

हालाँकि, बड़ौदा डेयरी ने सभी स्थानों पर आपूर्ति पहुंचाई। वडोदरा में बड़ौदा डेयरी की 112 गाड़ियों से रोजाना 4.50 लाख लीटर दूध की सप्लाई होती है. वडोदरा शहर के आधे हिस्से में बाढ़ की स्थिति के बावजूद बड़ौदा डेयरी ने आज 102 वाहनों के माध्यम से दूध की आपूर्ति की। साथ ही विभिन्न पुलों पर जहां जाना संभव नहीं था वहां आठ से दस टैंपा लगाकर दूध का वितरण किया। डेयरी सूत्रों ने बताया कि आज रोजाना से 10 हजार कम दूध बांटा जा सका.

वडोदरा मंडल पर कई जगह पर बाढ़ से ट्रेन यातायात प्रभावित जन सहयोग से जनसेवा के लिए आगे आए सामाजिक संगठन यात्रियों को खानपान सामग्री उपलब्ध कराई

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर वर्तमान परिस्थितियों में कई जगह पर भारी बरसात एवं बाढ़ जैसे हालात के कारण ट्रेन आवागमन बाधित हुआ है। इसी दौरान मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कई सामाजिक संगठनों ने अल्प सूचना पर तुरंत रेल यात्रियों को खानपान की सुविधाएं उपलब्ध कराकर सराहनीय कार्य किया है।

नर सेवा- नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए रे